लेह में जेन जेड और अरब स्प्रिंग स्टाइल में फैलाई गई हिंसा

अहिंसा का पैरोकार राजनीतिक महात्मा

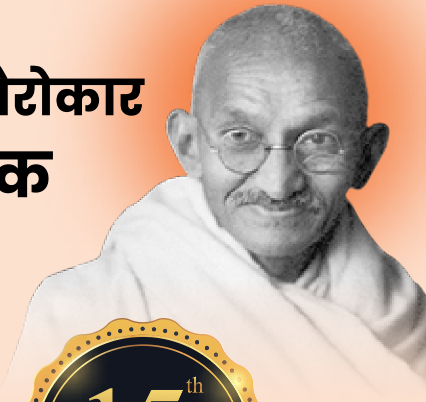

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 19 | मूल्य 15 रुपये | 28 सितंबर-04 अक्टूबर, 2025

पेपर लीक खत्म करने को सीएम धामी का "निर्णायक मिशन"

वर्ष 15 | अंक 19

दिव्य हिमगिरि

28 सितंबर-04 अक्टूबर, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वारः डॉ. रजनीश गौतम
पौडीः रत्नमणि भट्ट
कोटद्वारः के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुरः हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोलीः मुकेश रावत
रुड़कीः श्रीगोपाल नारसन
नैनीतालः शीतल तिवारी
अल्मोड़ाः संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगरः अजय शर्मा
प्रसारः रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादकः कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमा

अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का जीवन-तत्त्व है। अगर किसी भी वजह से इस अधिकार को बाधित किया जाता है, तो इसका अंतिम नुकसान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगा। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, जब किसी व्यक्ति की टिप्पणी को उसकी अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति की छवि को चोट पहुंचाती दिखती है। शायद यही वजह है कि कई बार अभिव्यक्ति की सीमा का भी सवाल उठाया जाता रहा है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, जिनमें किसी टिप्पणी को कोई व्यक्ति अपनी मानहानि के तौर पर देखता है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। यानी यह संभव है कि एक व्यक्ति के अपने विचारों की अभिव्यक्ति को कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की श्रेणी में रखा जाए। मगर यह भी सच है कि इससे संबंधित कानून को स्वतंत्र आवाजों को दबाने और गैरजरूरी तरीके से परेशान करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए इस संबंध में जो कहा है, वह अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में बेहद अहम साबित हो सकता है। एक समाचार वेबसाइट से जुड़े मामले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपराधिक मानहानि को अब अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। अदालत की यह टिप्पणी संबंधित वेबसाइट पर वर्ष 2016 में प्रकाशित एक लेख को लेकर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सामने आई। भारत उन देशों में है, जहां मानहानि को कानून अपराध माना जाता है। हालांकि कुछ अन्य देशों में यह मामला केवल नागरिक विवाद है, जिसमें मुआवजे की मांग की जा सकती है। भारत में इससे संबंधित कानून का असर इस रूप में देखा जाता है कि अक्सर राजनीतिक स्तर पर किसी संदर्भ में दो पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो उसमें कोई एक पक्ष आरोपों को अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि बता कर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, जिनमें वास्तव में जानबूझ कर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस आरोप में घिरे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत का कोई मजबूत आधार नहीं पाया जाता। वहीं इस कानून के तहत दर्ज मुकदमों के जरिए स्वतंत्र स्वरों को बाधित करने के मामले आम पाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कसौटी पर रखा है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2016 में शीर्ष अदालत ने ही एक मामले में आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। अब इसी अदालत ने जिस तरह मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाने की बात कही है, उसके अपने आधार हैं। यह छिपा नहीं है कि इस कानून का सहारा लेकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। कई बार किसी ऐसी टिप्पणी को भी मानहानिकारक बता दिया जाता है, जो तथ्यों पर आधारित होती हैं या उससे कोई बहस खड़ी हो सकती है। इस बात की संभावना हो सकती है कि कोई व्यक्ति किसी खास बयान या समाचार को अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला माने, लेकिन अगर वह बयान या समाचार व्यापक जनहित के सवालों से जुड़ा है, तो उस पर विचार किया जाना और सही पक्ष सामने लाना देश की लोकतांत्रिक जड़ों को ही मजबूत करेगा

कुँवर राज अस्थाना

सुरक्षित भारत, शक्तिशाली भारत

किसी विचारक का कहना है कि तुम्हारा अच्छे से अच्छा सिद्धांत व्यर्थ है, अगर तुम उसे अमल में नहीं लाते। हमारी सुरक्षा चिंताओं से संबंधित कानूनों की भी एक दशक पहले तक यही स्थिति रही है। वर्ष 1947 में तैयार राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को अभी तक ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सका है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ज्यादा जाना जाता रहा है। देश को भीतरी-बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए बने ऐसे तमाम कानून कभी उन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पाए, जिनके लिए उनका निर्माण किया गया था। इसके पीछे ईमानदार प्रयासों की कमी रही हो या इच्छाशक्ति की, या फिर दोनों की, देश ने आजादी के बाद के छह दशकों में बहुत कुछ सहा है। सीमाओं के भीतर भी और सीमाओं पर भी।

संकल्पशक्ति से उपजे फैसले

बारह साल पहले, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार सत्ता में आई, तो कुछ ही समय बाद उसने दिखा दिया कि वह देश की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। इस क्रम में वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय रक्षा योजना समिति (डीपीसी) का गठन एक अच्छी शुरुआत रही है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने के लिए गठित किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अलावा डीपीसी के प्रमुख उद्देश्यों में क्षमता संवर्द्धन योजना का विकास, रक्षा रणनीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काम करना और भारत में रक्षा उत्पादन ईकोसिस्टम को उन्नत बनाना आदि शामिल हैं।

एक राष्ट्र का सम्मान, प्रभुत्व और शक्ति इसमें निहित है कि वह भीतरी और बाहरी चुनौतियों से निपटने में कितना सक्षम है और किसी भी संभावित खतरे से कितना सुरक्षित है। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने एक राष्ट्र की सम्प्रभुता के लिए खतरा साबित होने वाली इन चुनौतियों की चार श्रेणियां निर्धारित की थीं। भीतरी खतरे, बाहरी खतरे, बाहरी सहायता से पनपने वाले भीतरी खतरे और भीतर से सहायता पाकर मजबूत होने वाले बाहरी खतरे। लगभग यही खतरे आज भी नक्सलवाद, अलगाववाद, सीमा पर चलने वाली चीनी-पाकिस्तानी गतिविधियों, आतंकवाद, स्लीपर सेल आदि के रूप में सिर उठाते रहते हैं। नए दौर में इनके अलावा भी और कई सुरक्षा चुनौतियां हैं, जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। इनमें आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे और भी कई मुद्दे शामिल हो चुके हैं, जिनके तार भीतर ही भीतर एक-दूसरे से जुड़े हैं।

2014 में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक जबरदस्त बदलाव हुआ और देश को एक मजबूत इरादों वाली मजबूत सरकार मिली, जिसका नेतृत्व 21वीं सदी के विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा था। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देश में चीजें तेजी से बदलना शुरू हुईं। प्रधानमंत्री जी की दूरशिता और अथक प्रयासों के नतीजे हम लगभग हर क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में देख रहे हैं। अगर हम एक दशक पहले की परिस्थितियों से तुलना करें तो आज भारत की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता को चुनौती देने वाले तमाम तत्व निरूशक्त और सहमे-सहमे से नजर आते हैं। आतंकवाद और सीमापार से होने वाली राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है, तो देश के भीतर चलने वाली नक्सलवादी/ वामसमर्थित अलगाववादी गतिविधियों पर भी लगाम लगी है।

यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियों और उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण देश के विभिन्न भागों, खासकर कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, के भीतर दशकों से पनप रहे असंतोष के स्वरों को भी शांतिपूर्ण और स्वीकार्य उपायों से समाधान उपलब्ध कराने में हमें उल्लेखनीय सफलता मिली है।

सही समय पर सही फैसले

इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व को, जिसमें सही समय पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरी दृढ़ता के साथ लागू करने की इच्छाशक्ति भी मौजूद है। चाहे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाली एकतरफा कार्रवाईयों के विरुद्ध मजबूती से खड़े होने का मामला हो या शक्ति संतुलनों के नए समीकरणों में भारत के प्रति मानसिकता और पुरातन सोच में बदलाव लाने का। आज न सिर्फ हम एकध्रुवीय दुनिया में अपने हितों की रक्षा में सफल रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व, इस तेजी से बदलती व्यवस्था में भारत की नई सशक्त और निर्णायक भूमिका को स्वीकार कर रहा है। भारत की भीतरी मजबूती और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी सख्ती और जीरो टॉलरेंस अप्रोच के साथ हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की 'सॉफ्ट स्टेट' वाली छवि को तोड़ने में सफल रहे हैं।

रणनीतिक स्पष्टता और त्वरित निर्णय लेने की सामर्थ्य के साथ, भारत ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही अपनी मजबूती और बढ़त बनाई है, बल्कि वर्तमान और भावी सुरक्षा चुनौतियों

से निपटने के लिए भी भरपूर तैयारियां की हैं। इनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्षमता निर्माण आदि शामिल है। राष्ट्रीय हित में राजनीति से ऊपर उठकर हमने निष्पक्ष पेशेवरों और विशेषज्ञों की मदद से योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर विकास को गति देने के लिए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की, जिसके अंतर्गत 2019-20 के दौरान 11,400 किमी सड़कें बनाई गई और सीमावर्ती क्षेत्रों में छह पुलों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा नागरिक-सैन्य सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दोहरे इस्तेमाल वाला इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया। रक्षा मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समन्वय से चिन्हित राजमार्गों के 29 हिस्सों को आपात एयरवे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने योग्य बनाया। 30 सैन्य हवाई क्षेत्रों में सात एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए गए।

इसी प्रकार स्वतंत्र और समन्वित राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का विकास और एक इंटेलीजेंस ग्रिड का निर्माण कर हमने अपने इंटेलीजेंस आधारित अभियानों में तेजी लाई है। आज आशंकाओं को वास्तविकता में बदलने से पहले, सूचना मिलते ही तुरंत उन पर कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा एजेंसियों में बेहतर तालमेल, सुव्यवस्थित सुधारों और कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से आतंकवाद से निपटा गया है। अगर हम श्री मोदी के देश की बागडोर संभालने से पहले के दस सालों की बात करें, तो पाएंगे कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच देश में 25 बड़े आतंकवादी हमले हुए, जिनमें एक हजार से अधिक मौतें हुई और करीब तीन हजार लोग घायल हुए। लेकिन, 2014 के बाद से नागरिक क्षेत्रों में कोई भी बडी आतंकवादी वारदात नहीं हुई है।

नेटवर्क पर प्रहार, वित्तीय स्रोतों का सफाया

देश भर में अभियान चलाकर सौ से अधिक आतंकवादियों को पकड़ा गया। उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले संस्थानों पर रोक लगाई गई और देश में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे सिमी, जेएमबी, एसएफजे, इस्लामिक फ्रंट और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के वित्तीय स्रोत खत्म कर उनकी रीढ़ तोड़ी गई। इसके अलावा मित्र देशों के समर्थन का विस्तार करते हुए इन संगठनों के नेटवर्क पर प्रहार कर इसे कमजोर किया गया। यह हमारे खुफिया तंत्र की एक बड़ी सफलता थी कि

हमने अलकायदा मॉडयूल को समय रहते पहचान कर, भारत में उसकी जड़ें जमने ही नहीं दीं। सेना को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई तो उनका मनोबल बढ़ा और उनके अभियानों में तेजी आई।

इसी क्रम में केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर इंटेलीजेंस बेस्ड कोऑर्डिनेशन स्थापित कर वामपंथ समर्थित अतिवादियों और भारत विरोधी प्रोपगंडा चला रहे अर्बन नक्सलियों के विरुद्ध सैन्य व वैचारिक अभियान चलाकर उनके हौसले पस्त किए गए और प्रोपेगंडा को कमजोर करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया। अशांत पूर्वोत्तर राज्यों में 2019 में त्रिपुरा समझौता, जनवरी 2020 में त्रिपुरा-मिजोरम सीमा विवाद का निपटारा, इसी साल असम समझौता कर और मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में अफसा हटाकर वहाँ शांति स्थापित की गई।

अगर हम सीमाओं की सुरक्षा की बात करें तो हमने चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पारंपरिक विरोधियों को कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर कड़ी चोट दी है। 2016 में उरी अटैक के बाद पीओके में हमारी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद हमारी बालाकोट एयर स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि यह भारत वह भारत नहीं है, जो उसकी परमाण ु बम की गीदड़ भभकी से डरकर, सख्ती से परहेज बरतता था। इसी प्रकार 2014 में एलएसी पर चीन की भड़काऊ गतिविधियों और 2017 में डोकलम में 1500 चीनी सैनिकों की घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने में भी हमने भरपूर राजनीतिक इच्छाशक्ति और कूटनीतिक सामर्थ्य का परिचय दिया। यही वजह थी कि चीन को बैकफुट पर आना पड़ा।

रक्षा सुधारों और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से बढ़ी ताकत

हमारी इस बढ़ती ताकत और प्रभाव के पीछे हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की भी एक अहम भूमिका रही है। हमने ब्रिटेन, अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ सामरिक भागीदारी कर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया है। चीन की विस्तारवादी गतिविधियों से निपटने में भूटान की सहायता की है, बांग्लादेश से संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते हुए लंबे समय से लटके सीमा विवाद को निपटाया है।

रक्षा क्षेत्र को और मजबूत व चुस्त बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का पुनर्गठन कर भूमिकाओं और कार्यो का व्यावहारिक आवंटन कर इन्हें संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे अपारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे बाहरी, आंतरिक, खुफिया, साइबर और सैन्य कार्रवाईयों से संबंधित तंत्र व संरचानाओं को मजबूती मिलेगी।

ये कुछ बानगियां हैं, उन असंख्य बदलावों की, जो हमने पिछले एक दशक में घटते देखे हैं। इन्हीं का नतीजा है कि नया भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है, जो अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करता और चुनौतियां चाहें भीतरी हों या बाहरी, उनका कठोर जवाब देने में समर्थ है।

(लेखक: भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग में आचार्य और अध्यक्ष हैं)

पेपर लीक खत्म करने को सीएम धामी का "निर्णायक मिशन"

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

बड़े और सख्त फैसलों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के सामने 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक कांड सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। पेपर लीक ने न केवल हजारों युवाओं के भविष्य पर पानी फेर दिया है, बल्कि धामी की स्वच्छ छवि और सरकार की साख पर भी गहरी चोट की है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर उमड़ा युवाओं का गुस्सा, विपक्ष के तीखे हमले और दिल्ली दरबार तक गूंजती इस आंच ने साबित कर दिया है कि यह मामला अब सिर्फ परीक्षा का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब जेल ही ठिकाना बनेगा। एसआईटी की तेज जांच से हर गुनहगार को बेनकाब कर सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने इसे 'पेपर जिहाद' करार देते हुए निर्णायक जंग का एलान जरूर किया है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और देहरादून के डीएम-एसएसपी जैसे वरिष्ठ अफसरों के सीधे निगरानी में होने के बावजूद सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई?

आपदा से कराहती देवभूमि में राहत-बचाव और पुनर्वास में पूरी तरह व्यस्त धामी सरकार और प्रशासन के सामने 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक कांड एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया। पेपर लीक कांड ने न केवल हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधेरे में डाल दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वच्छ छवि और सरकार की साख पर भी करारा धक्का लगाया। सीएम धामी ने इस चुनौती को 'पेपर जिहाद' करार देते हुए अब निर्णायक मिशन का एलान किया है। लेकिन इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि सिस्टम की दीवारें अभी उतनी मजबूत नहीं हुई हैं जितनी जनता अपेक्षा कर रही थी। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे सरकार की छवि पर धब्बा बताया और अब यह मुद्दा दिल्ली भी पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक की हर पिछली घटना पर त्वरित कार्रवाई की थी और दावा किया था कि उत्तराखंड से नकल माफिया की जड़ें काट दी गई हैं। लेकिन 21 सितंबर की घटना ने उन तमाम दावों को सवालों के घेरे में ला दिया है।

यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि सरकार की साख और भरोसे का संकट बन गया है। जिस समय धामी सरकार आपदा प्रबंधन में जुटी थी, ठीक उसी दौरान इस तरह की वारदात होना जनता के लिए यह संदेश देता है कि माफिया अब भी सक्रिय हैं और सिस्टम को भीतर से खोखला कर रहे हैं। धामी सरकार ने इस मसले को हल्के में न लेने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने तुरंत मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, देहरादून के तेजतर्रार डीएम सविन बंसल

पेपर लीक पर धामी सरकार के खिलाफ देहरादून में युवाओं ने किया प्रदर्शन

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद राजधानी देहरादून में सैकड़ों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। राजधानी के गांधी पार्क से घंटाघर तक निकाले गए जुलूस में शामिल अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवाओं ने कहा कि उन्होंने सालों मेहनत की, रात-दिन पढ़ाई की, लेकिन पेपर लीक की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और युवाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। युवाओं ने विधानसभा घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। युवाओं का कहना था कि सरकार हर बार 'कड़े कदम' उठाने का दावा करती है, लेकिन नकल माफिया बार-बार सक्रिय होकर भर्ती परीक्षाओं को कलंकित कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने युवाओं के समर्थन में उतरते हुए धामी सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार नकल माफियाओं पर सिर्फ दिखावटी कार्रवाई करती है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस पूरे घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या उच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। युवाओं का आरोप है कि जब मुख्यमंत्री धामी खुद इस मामले को 'पेपर जिहाद' कह चुके हैं, तब सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आखिर माफिया किसकी शह पर बार-बार सक्रिय हो जाते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि मामले की विशेष जांच टीम काम कर रही है और एक महीने के भीतर जांच पूरी करने का प्रयास होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने पेपर लीक केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। लेकिन युवाओं का कहना है कि एसआईटी का रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं है। पिछले 9 बड़े मामलों में से 8 में न तो दोषियों को सजा हुई और न ही जांच पूरी हुई।

ऐ एसएसपी अजय सिंह को निर्देश दिए हैं कि पूरे नेटवर्क को उजागर कर कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री को भरोसा है कि इन वरिष्ठ अफसरों का अनुभव और ईमानदारी इस संगठित गिरोह की कमर तोड़ने में मदद करेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जब इतने सख्त आदेश पहले से लागू थे, तब यह घटना कैसे हो गई? यही वजह है कि आलोचकों का कहना है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। पेपर लीक कांड की आंच अब राज्य की सीमाओं से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। राजनीतिक रूप से भी इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है और मांग कर रहा है कि दोषियों को केवल पकड़ा ही न जाए, बल्कि कठोर सजा भी मिले ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिमाकत न कर सके। एसआईटी की गठन, तकनीकी निगरानी, कड़े प्रशासनिक नियंत्रण और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई को लेकर सीएम धामी ने आश्वासन दिया है।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का जेल ही ठिकाना बनेगा: सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने इस पूरे कांड को 'पेपर जिहाद' बताते हुए साफ किया है कि अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह सिर्फ कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत और भविष्य की रक्षा का सवाल है। उत्तराखंड में नकल और पेपर माफियाओं के दिन लद चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब जेल ही ठिकाना बनेगा। एसआईटी की तेज जांच से हर गुनहगार को बेनकाब कर सख्त सजा दी जाएगी। सीएम धामी युवाओं को न्याय और पारदर्शिता देने के अपने वादे पर अडिग हैं। धामी सरकार का लक्ष्य अब सिर्फ दोषियों को पकड़ना नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और अभेद्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस विशेष जांच टीम को सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में काम करने का आदेश दिया है, ताकि निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठ सके। इस टीम के साथ-साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी सीधे रिपोर्ट ली है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, और वह इस जांच को एक महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, और यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक ने न केवल युवाओं के सपनों को तोड़ा है बल्कि धामी सरकार की छवि पर भी गहरी चोट पहुंचाई है। इस पेपर लीक कांड में कई सवाल अब तक अनसुलझे हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोबाइल एक्जाम सेंटर के भीतर कैसे पहुंचा। आयोग का दावा था कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी हो रही थी। नियम स्पष्ट थे कि एडमिट कार्ड, पेन, पैसे और गाड़ी की चाबी के अलावा कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। अंगूठी और चेन तक बाहर रखवाई जा रही थी। फिर भी हरिद्वार के बहादरपुर जट गांव स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से पेपर मोबाइल के जरिए बाहर भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल यही है

जब इतनी सख्ती थी, तो मोबाइल सेंटर के भीतर कैसे पहुंच गया? अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री और उनके शासन पर हैं। क्या विशेष जांच टीम की पड़ताल और कठोर कार्रवाई से जनता का भरोसा लौटेगा, या फिर यह मुद्दा धामी सरकार की राजनीति और साख के लिए संकट बन जाएगा, यही आने वाला समय तय करेगा।

धामी सरकार ने पेपर लीक मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रोफेसर को किया सस्पेंड

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। हरिद्वार में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इसके अलावा, टिहरी के अगरोड़ा कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी पेपर हल कर भेजने में संलिप्त पाए जाने के कारण निलंबित किया गया। वहीं बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर डयूटी में तैनात एक दारोगा और एक कांस्टेबल को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। एसएसपी हरिद्वार ने आरोपी दरोगा रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को निलंबित किया और मामले की जांच सीओ रुड़की को सौंपी है। (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित रूप से लीक होने का मामला 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से सामने आया था। इस मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, खालिद ने हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव में स्थित परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र की फोटो लेकर अपनी बहन साबिया को भेजी। साबिया ने इन प्रश्नों को टिहरी की एक सहायक प्राफेसर सुमन तक पहुंचाया, जिन्होंने इन उत्तरों को हल कर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराए। हालांकि, सुमन को कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ। उन्होंने इन स्क्रीनशॉट्स की जानकारी एक अन्य व्यक्ति से साझा की। उस व्यक्ति ने इसे सीधे पुलिस या किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके चलते प्रश्नपत्र तेजी से फैल गया। राज्य सरकार ने इस यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) गठित किया है। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी दोषियों और लापरवाह कर्मचारियों की पहचान की जा सके।

आंदोलनरत छात्रों को प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन देते हुए देहरादून के डीएम और एसएसपी

पेपर लीक कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला

उत्तराखंड में 21 सितंबर को हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक कांड के बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को 'पेपर चोर' करार देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी ने कहा, आज भाजपा का दूसरा नाम 'पेपर चोर' है। देशभर में बार-बार हो रहे पेपर लीक ने लाखों मेहनती युवाओं के सपनों और मेहनत को चुराया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में हुई यह घटना इसका ताजा उदाहरण है, जहां लाखों युवाओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन भाजपा ने उनकी मेहनत को चोरी करके नष्ट कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं की बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि केवल सत्ता बनाए रखने में लगी है। उन्होंने कहा, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन सरकार इस पर आंखें मूंदे बैठी है। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो 'वोट चोरी' से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने कहा, पेपर चोर जानते हैं कि अगर युवाओं को नौकरियां नहीं मिलतीं, तो वे चुनावों में वोट चुराकर सत्ता में बने रहेंगे। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की कि वे इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें और इसे केवल नौकरी की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई मानें। उन्होंने 'पेपर चोर, गद्दी छोड़' का नया नारा भी दिया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने राज्य में आयोजित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा में एक बार फिर सामने आए पेपर लीक मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ धामी सरकार का एक और बड़ा धोखा है। करन माहरा ने कहा कि धामी सरकार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 जारी कर इसे देश का सबसे सख्त नकल-विरोधी कानून बताया था। सरकार ने दावा किया था कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए वह नकल माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकते हुए पारदर्शी भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। करन माहरा ने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं का पाला हुआ नकल माफिया हाकम सिंह बार-बार युवाओं के भविष्य से किसकी शह पर खेल रहा है? कौन है हाकम सिंह का 'हाकिम' जो इस नकल माफिया का 'गॉडफादर' बनकर निरंतर इस नेटवर्क को फलने-फूलने दे रहा है? करन माहरा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसका पुरजोर विरोध करेगी और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

आई लव मोहम्मद की हकीकत और साज़िशों का सच

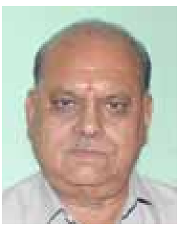

अजय कुमार,
वरिष्ठ पत्रकार

इस्लाम धर्म में बुतपरस्ती यानी मूर्तिपूजा को कड़ाई से हराम घोषित किया गया है। पैग़म्बर साहब की किसी तस्वीर, चित्र या मूर्ति बनाने पर हमेशा से पाबंदी रही है, क्योंकि इस्लाम का मूल संदेश एक ईश्वर की इबादत पर आधारित है, न कि किसी प्रतिमा या चित्र की पूजा पर। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में नए तरह का चलन देखने को मिल रहा है, जिसमें जगह-जगह आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मोहम्मद साहब के नाम पर समाज का माहौल खराब करने सहित दंगा फैलाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब पैगम्बर की तस्वीर तक बनाना मना है, तब क्या इस तरह के भावनात्मक नारे लगाकर धार्मिक और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें जायज़ मानी जा सकती हैं? पैग़म्बर मोहम्मद साहब ने अपने जीवनकाल में तौहीद का संदेश दिया था। उन्होंने हर तरह की बुतपरस्ती और चित्र या मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन आई लव मोहम्मद जैसी कार्यवाहियाँ इस्लाम की उसी मूल भावना से टकराती नज़र आती हैं। यहाँ सवाल यह नहीं कि मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम या आदर किया जा रहा है, बल्कि यह है कि उस प्रेम को किस रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस्लाम में अपने पैग़म्बर से मोहब्बत दिखाने का तरीका उनके बताए मार्ग पर चलना और अमल करना है, न कि नारेबाज़ी और पोस्टरों से हंगामा खड़ा करना। कानपुर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जो चिंगारी निकली थी बरेली में उसने उग्र रूप धारण कर लिया। उपद्रवियों ने जम कर हिंसा और लूटपाट की। इस अराजकता के लिये विवादित मुस्लिम मौलाना तौकीर रजा सीधे तौर पर उतरदायी है। बरेली में तौकीर रजा सहित दंगा फैलाने वालों पर कार्रवाई के बाद इस समय वहां तनावपूर्ण शांति है।

बीते कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, दीवारों पर बने बड़े-बड़े बैनर और झंडे देखने को मिल रहे हैं। इन बैनरों को लगाने का नाम भले ही धार्मिक प्रेम दिखाना बताया जा रहा हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक नीयत छिपी हुई है। यह सिर्फ साधारण नारा नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी साज़िश है जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काकर समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है। इन बैनरों का उद्देश्य केवल अपने समुदाय में धार्मिक जोश जगाना नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों को उकसाना भी है। सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने वाले ये पोस्टर जब किसी अन्य संप्रदाय के इलाके में लगाए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से टकराव की स्थिति बनती है। उत्तर प्रदेश के कई कस्बों और शहरों में यही देखने को मिला। मोहल्लों में एक वर्ग जब आई लव मोहम्मद के झंडे या बैनर लेकर निकलता है, तो दूसरा वर्ग इसे उकसावे की कार्रवाई मानता है। धीरे-धीरे माहौल गरमाने लगता है और छोटे-छोटे विवाद बड़े दंगों में बदल जाते हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लंबे समय से धार्मिक तनावों को लेकर चुनौती झेल रही है। प्रशासन अक्सर नारे लगाने और पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाता, क्योंकि इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बना दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस्लामी शिक्षाओं में चित्र और मूर्ति जैसी चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, तो फिर इन पोस्टरों को धार्मिक स्वतंत्रता कैसे माना जा सकता है? यह स्पष्ट है कि प्रशासन की शिथिलता के कारण ही ये साज़िशें परवान चढ़ रही हैं। धार्मिक नारों और बैनरों का दूसरा बड़ा पहलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। हर चुनावी मौसम में समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काकर वोट पाना एक आम चलन बन चुका है। आई लव मोहम्मद आंदोलन भी यही खेल लगता है। आम लोगों की आस्था को हथियार बनाकर न केवल वातावरण दूषित किया जा रहा है, बल्कि दंगे-फसादों का डर दिखाकर राजनैतिक गोलबंदी भी की जा रही है। इन घटनाओं के कारण समाज के आम नागरिक लगातार दहशत में जी रहे हैं। जिन इलाकों में पोस्टर लगाए जाते हैं, वहां तनाव फैल जाता है। दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और छोटे-छोटे बच्चों तक के मन में डर बैठ जाता है। बड़ों के दिमाग में यह सवाल गूंजता है कि यह प्यार दिखाने का तरीका है या दंगे भड़काने की चाल?

वहीं कई मुस्लिम विद्वानों ने खुलकर कहा है कि इस तरह के नारे और बैनर इस्लामी शिक्षा के खिलाफ हैं। पैग़म्बर मोहम्मद साहब से असली प्रेम उनका आदर्श जीवन अपनाने में है, न कि झंडे और पोस्टर लहराने में। लेकिन यही धार्मिक संदेश जब तक आम जनता तक सही रूप में नहीं पहुंचेगा, तब तक ये साज़िशें जारी रहेंगी। भारत का इतिहास धार्मिक उन्माद और दंगों से भरा पड़ा है। छोटी-सी चिंगारी बड़े विस्फोट में बदल जाती है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक, फूट डालो और राज करो की नीति बार-बार दोहराई जाती रही है। फर्क बस इतना है कि अब राजनीति करने वाले आधुनिक तरीकों से यही काम कर रहे हैं। पोस्टर, बैनर और नारे इसी आधुनिक हथियार का हिस्सा हैं।

बहरहाल, कुल मिलाकर इस्लामी विद्वानों को आम जनता को समझाना होगा कि मोहम्मद साहब के नाम का उपयोग राजनीतिक मंसूबों के लिए करना पाप है। असली अनुसरण उनके जीवन मूल्यों को अपनाने में है। किसी भी समुदाय की आस्था की आड़ लेकर शहर की शांति बिगाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक नारेबाज़ी के नाम पर पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

लेह में जेन जेड और अरब स्प्रिंग स्टाइल में फैलाई गई हिंसा

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार

लेह-लद्दाख में हालिया हिंसक घटनाएं न केवल स्थानीय राजनीतिक सरगर्मियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कांग्रेस के संभावित संबंधों, विदेशी हस्तक्षेप, और केंद्र सरकार से असंतोष के मुद्दों को भी सामने ला रही हैं। सोनम वांगचुक, लद्दाख क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने और छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल 10 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी और कई नेताओं व प्रशासन के आग्रह के बावजूद वे अनशन पर डटे रहे। इस दौरान गिन-चुन कर चुने गए भाषणों में वांगचुक ने नेपाल के जेन जी मूवमेंट और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र किया और युवाओं को उससे प्रेरण ाा लेकर आगे आने को कहा। यही तथ्य केंद्र सरकार के मुताबिक हिंसा के पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। पुलिस और प्रशासन के कार्यालयों सहित बीजेपी के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई। प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है तथा सीआरपीएफ, पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की तैनाती की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वांगचुक अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से मुलाकात करने वाले थे, उससे दो-तीन दिन पहले उन्होंने लद्दाख को हिंसा की आग में किस साजिश के तहत झोंक दिया। इस हिंसा के पीछे कांग्रेस की भूमिका को लेकर तीखे आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय कांग्रेस पार्षद फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग ने सीधे तौर पर हिंसक घटनाओं का मार्गदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर त्सेपाग को आरोपी बनाया है और कांग्रेस के संबंध को लेकर तस्वीरें, वीडियो भी जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है और सोनम वांगचुक भी अपने ऊपर लगे उकसावे के आरोपों का खंडन कर चुके हैं।

सरकार और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के अनुसार, आंदोलन के दौरान जब वांगचुक ने अपने भाषण में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन-जेड आंदोलनों का उल्लेख किया, उससे आंदोलनकारी युवा वर्ग खास तौर पर प्रेरित हुआ। इस संदेश के चलते युवा प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश में आकर सरकारी इमारतों, बीजेपी कार्यालयों और वाहनों पर हमला किया। जो भीड़ पहले शांतिपूर्वक अनशन स्थल पर थी, उसने बाद में हिंसक प्रदर्शन किए। इस पूरी प्रक्रिया को कुछ रिपोर्टों में सुनियोजित और योजनाबद्ध बताया गया है, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधियों के निजी स्वार्थों और साजिश की भी चर्चा हुई है। वैसे सोनम वांगचुक की छवि एक शिक्षावादी और पर्यावरण योद्धा की रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक टिप्पणियां और बाहरी मंचों पर दिए गए भाषण चर्चाओं में रहे हैं। फरवरी 2025 में उनकी पाकिस्तान यात्रा पर भी सवाल उठे थे, जहाँ वे एक पर्यावरण सम्मेलन में शामिल हुए थे। उस यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किए गए बयानों पर कई बार विवाद हुआ कि कहीं किसी देश-विदेश की प्रेरणा या संसाधनों की भूमिका तो नहीं। वांगचुक की ये जन जागरूकता-आधारित राजनीति अक्सर जोखिम भरी मानी जाती है क्योंकि वह बार-बार युवाओं से संगठित प्रतिरोध या गांधी के मार्ग की जगह अधिक आक्रामक रुख अपनाने की अपील कर चुके हैं।

उधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन इस हिंसा और उसके पीछे की संभावित विदेशी ताकतों की भूमिका को लेकर हर एंगल से जांच कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की पाकिस्तानी संपर्कों वाली यात्रा, 'अरब स्प्रिंग' और 'नेपाल-जेन-जेड' आंदोलनों पर बार-बार जोर, और भीड़ के हिंसक हो जाने की तमीज़ को शक की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष विदेशी फंडिंग या दखल की पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिंसा के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी बताते हुए स्थानीय पार्षद फुंटसोग स्टैनजिन त्सेपाग का नाम और सबूत मीडिया प्रमोशन में इस्तेमाल किए हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस और इसके स्थानीय नेताओं ने युवाओं को खास दिशा में उकसाया जिससे स्थिति बेकाबू हुई। वहीं, कांग्रेस नेतृत्व ने इन दावों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी के खिलाफ साजिश की बात कही है।

जीवनधारा नदियों के लुप्त होने का खतरा: संरक्षण का संकल्प

ललित गर्ग

नदियां मात्र जलधाराएं नहीं हैं, वे जीवन की धमनियां हैं, सभ्यता की जननी हैं और प्रकृति का शाश्वत उपहार हैं। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि हर संस्कृति और हर महान नगरी का उदय नदियों के तट पर हुआ। गंगा, सिंधु, नील, अमेज़न, यांग्त्सी जैसी नदियाँ केवल भूगोल का निर्माण ही नहीं करतीं, बल्कि कृषि, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, आस्था और संस्कृति को भी दिशा देती हैं। विश्व स्तर पर हर वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाने वाला विश्व नदी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि नदियां हमारी अस्तित्व-रेखा हैं और उनका संरक्षण करना किसी विकल्प का नहीं बल्कि हमारे जीवन के अस्तित्व का प्रश्न है। 2005 में, संयुक्त राष्ट्र के 'जीवन के लिए जल दशक' की शुरुआत के उपलक्ष्य में, नदी अधिवक्ता मार्क एंजेलो ने विश्व नदी दिवस के गठन का प्रस्ताव रखा। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कनाडा में 1980 में एंजेलो द्वारा शुरू किए गए बीसी नदी दिवस की सफलता से प्रेरित था। विश्व नदी दिवस नदियों के महत्व को रेखांकित करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नदियों की बेहतर देखभाल-संरक्षण-संवर्धन का समर्थन करते हुए जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस वर्ष की थीम 'हमारी नदियाँ, हमारा भविष्य' है, जो नदियों की रक्षा, जल अधिकारों को बनाए रखने और नदी प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की आवाज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 65 प्रतिशत पेयजल नदियों से आता है, इसी तरह भारत सहित अनेक देशों में पेयजल का मुख्य स्रोत नदियां ही है। नदियां हमें बिजली पैदा करने, फसलों को पानी देने और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती हैं। यही कारण है कि एम्स्टर्डम, बैंकॉक और बर्लिन जैसे समृद्ध शहर नदियों के किनारे बसे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिन नदियों ने हमें जीवन दिया, हमने उन्हीं को प्रदूषण और विनाश की गर्त में धकेल दिया। औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक कचरा, नगरों का गंदा पानी, प्लास्टिक और घरेलू अपशिष्ट ने नदियों को गटर में बदल दिया है। अंधाधुंध बांध निर्माण और जलविद्युत परियोजनाओं ने उनकी प्राकृतिक धारा को बाधित किया है। धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के नाम पर मूर्तियों और अस्थियों का विसर्जन नदियों की पवित्रता को विषाक्त बना रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। भारत में गंगा, यमुना, चंबल, साबरमती जैसी नदियां इस प्रदूषण और शोषण का शिकार हैं, वहीं विश्व स्तर पर अमेज़न, नील और डेन्यूब जैसी नदियां भी प्रदूषण और अत्यधिक दोहन की मार झेल रही हैं। पृथ्वी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी जीविका के लिए मछलियों पर निर्भर है, इसलिए हमें औद्योगिक कचरे के कारण नदियों के क्षरण को सक्रिय रूप से रोकने और पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि जीव-जंतुओं और वन्य जीवन की धुरी हैं। असंख्य मछलियां, कछुए, पक्षी और जलीय प्राणी नदियों से अपना जीवन पाते हैं। जब

नदी प्रदूषित होती है तो यह जैवविविधता समाप्त होने लगती है, खेत बंजर हो जाते हैं, भूजल स्तर गिर जाता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। नदियों की मृत्यु वास्तव में पृथ्वी/सृष्टि की मृत्यु है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि नदियों के संरक्षण को हम केवल सरकारी योजनाओं या नीतियों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जनांदोलन का रूप दें। प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, शोधन संयंत्रों की अनिवार्यता और सामाजिक जागरूकता ही वे उपाय हैं जिनसे नदियों को नया जीवन दिया जा सकता है। गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे जैसी योजनाएँ तभी सार्थक होंगी जब समाज ईमानदारी से अपने हिस्से का कर्तव्य निभाएगा। नदियों को गंदा करना आत्मघात है और उन्हें बचाना जीवन रक्षा का संकल्प।

भारत में कई नदियां सूखने या प्रदूषित होने के कारण मरने के कगार पर हैं। इन नदियों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कुछ तो नालों में बदल गई हैं और उनका नदी होना भी मुश्किल है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण, तथाकथित भौतिकवादी सोच एवं नदियों के प्रति उपेक्षा एवं दोहन के कारण कई नदियां अब 'मृत' होने की कगार पर है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल हो चुकी है। नदियां के अत्यधिक ख़तरे में होने से मानव जीवन, पर्यावरण एवं प्रकृति भी संकट में है। जरूरत है मानसूनी जल को नदियों से जोड़ने एवं संरक्षित करने की। देश में सर्वत्र नदियों का अस्तित्व खतरे में है। विशेषत: उत्तर प्रदेश में नदियों की संख्या लगभग 1,000 है, जिनका 55 हजार किलोमीटर का नेटवर्क है। उनमें से 30 हजार किलोमीटर क्षेत्र में जल घटा है या सूखा है। प्रदेश की 100 छोटी और सहायक नदियां सूख चुकी हैं। बिहार की 50 से अधिक नदियां संकट में हैं। इनमें 32 बड़ी नदियां सूख चुकी हैं, जबकि 18 में पानी थोड़ा बचा है। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और यह अत्यधिक प्रदूषण और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण मरने के कगार पर है। साहिबी नदी, जो कभी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी थी। हैरानी की बात है कि गंगा, सोन और अघवारा जैसी बड़ी नदियों में भी पानी कम है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा-हल्द्वानी की लाइफलाइन कोसी और गौला नदियों का जलस्तर कम हो रहा है।

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के तरीकों में बदलाव आया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में

सूखे की स्थिति बढ़ गई है और नदियों में पानी का प्रवाह कम हो गया है। नदियों से रेत का अवैध खनन भी नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है और नदियों के बहाव को बदल रहा है। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे नदियों में गाद जमा हो रही है और उनकी गहराई कम हो रही है। भारत नदियों का एक अनोखा देश है जहां नदियों को पूजनीय माना जाता है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु (सिंधु), और कावेरी जैसी नदियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय, नदी घाटियों में आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार और संरक्षण और नदी प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। देश के समक्ष वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया गया है यानी आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है, जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं।

नदियां मानव अस्तित्व का मूलभूत आधार है और देश एवं दुनिया की धमनियां हैं, इन धमनियों में यदि प्रदूषित जल पहुंचेगा तो शरीर बीमार होगा, लिहाजा हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के बहाव को सुनिश्चित करना होगा। नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किये जाने की जरूरत है। देश में नदी जल एवं नदियों के लिए कानून बने हुए है, आवश्यक हो गया है कि उस पर पुनर्विचार कर देश के व्यापक हित में विवेक से निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारे राजनीतिज्ञ, जिन्हें सिर्फ वोट की प्यास है और वे अपनी इस स्वार्थ की प्यास को इस पानी से बुझाना चाहते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में गर्मी और लू के दिन जहां बढ़ रहे हैं, वहीं बरसात के दिन घटते जा रहे हैं। ऐसे में मानसूनी वर्षा के जल को यदि सलीके से नहीं सहेजा गया तो देश की सामाजिक-आर्थिक-प्राकृतिक स्थिति पर जल-संकट का बड़ा घातक प्रभाव होगा। विश्व नदी दिवस हमें यह चेतावनी देता है कि यदि नदियां सूख जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी तो मानव सभ्यता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नदियां हमारी जीवनरेखा और सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनका संरक्षण करना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और आशा को बचाना है। यह अवसर हमें यह संकल्प लेने का आहवान करता है कि हम नदियों को केवल उपयोग की वस्तु न समझें, बल्कि जीवित प्राणी की तरह उनका सम्मान करें, क्योंकि नदी बचेगी तो जीवन बचेगा, नदी बहेगी तो संस्कृति बहेगी।

सुपरफूड ऑफ इंडिया

डाइटिशियन वंदना,
फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट

सुपरफूड ऑफ इंडिया (हमारे रसोई घर की छुपी दवा)-
आज की तेज़-तर्रार ज़िंदगी में लोग हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह के सप्लीमेंट्स और महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की परंपरागत रसोई ही हमारी असली दवा है। हमारी दादी-नानी जिन खाद्य उत्पादों का रोज़ाना इस्तेमाल करती थीं, वे ही आज सुपरफूड कहलाते हैं। ये खाद्य उत्पाद न सिर्फ हमारे शरीर को पोषण देते हैं बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करते हैं। इस लेख में हम हल्दी, मेथी, रामदाना (अमरंथ), सत्तू, गोंद और मोरिंगा (सहजन) जैसे भारतीय सुपरफूड्स के वैज्ञानिक और परंपरागत फायदों पर चर्चा करेंगे।

1. हल्दी (सुनहरी एंटीसेप्टिक)-
परंपरागत उपयोग: हल्दी का इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से घाव भरने, त्वचा की देखभाल और संक्रमण रोकने के लिए होता आया है।
वैज्ञानिक दृष्टि: हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व है। पोषण मूल्यों की बात करें तो (100 ग्राम हल्दी में): कैलोरी 354, प्रोटीन 8 ग्राम, फाइबर 22 ग्राम, आयरन 55mg, मैंगनीज 7mg, विटामिन C 26mg
स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो
1 प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है
2 जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम
3 कैंसर-रोधी गुण
4 लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है।
कैसे लें: दूध में हल्दी डालकर 'गोल्डन मिल्क', सब्जियों या दाल में मसाले के रूप में।

2. मेथी- डायबिटीज की नैचुरल दवा
परंपरागत उपयोग: मेथी दाना को भिगोकर खाने से पाचन सुधरता है और शुगर लेवल नियंत्रित होता है।
वैज्ञानिक दृष्टि: इसमें 'गैलैक्टोमैनन फाइबर और ट्राइगोनेलिन' पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। पोषण मूल्यों पर जाऊं तो (100 ग्राम में): कैलोरी 323, प्रोटीन 23 ग्राम, फाइबर 25 ग्राम, आयरन 33mg, मैग्नीशियम 191mg
स्वास्थ्य लाभ:
1 डायबिटीज रोगियों के लिए वरदान
2 दूध बढ़ाने में सहायक (लैक्टेशन)
3 कब्ज और अपच दूर करता है
4 बालों और त्वचा के लिए लाभकारी
कैसे लें: अंकुरित मेथी दाना, सब्जी, पराठा, या दही के साथ पाउडर।

3. रामदाना (अमरनाथ)- प्रोटीन से भरपूर अनाज
परंपरागत उपयोग: व्रत में खाया जाने वाला रामदाना ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है।
वैज्ञानिक दृष्टि: इसमें 'लाइसिन (Lysine)' नामक आवश्यक अमीनो एसिड होता है, जो अधिकांश अनाजों में नहीं मिलता।
पोषण मूल्य (100 ग्राम में): कैलोरी 371, प्रोटीन 14 ग्राम, फाइबर 7 ग्राम, कैल्शियम 159mg, आयरन 7.6mg, मैग्नीशियम 248mg
स्वास्थ्य लाभ: ग्लूटेन-फ्री और हाई प्रोटीन कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर हड्डियों और रक्त निर्माण के लिए उत्तम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी
कैसे लें: चिल्ला, लड्डू, खीर, या आटे में मिलाकर रोटियाँ।

4. सत्तू (देसी प्रोटीन ड्रिंक)-
उपयोग- बिहार और उत्तर भारत में ''सत्तू का शर्बत'' गर्मियों में पिया जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टि- भुने चने से बना सत्तू प्रोटीन, फाइबर और आयरन का अच्छा स्रोत है।
पोषण मूल्य (100 ग्राम में): कैलोरी 413, प्रोटीन 22 ग्राम, फाइबर 11 ग्राम, आयरन 7mg, कैल्शियम 150mg
स्वास्थ्य लाभ:
ठंडक और एनर्जी देता है
ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है
पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है
वजन घटाने में सहायक
कैसे लें: नमकीन/मीठा सत्तू शर्बत, पराठा, लड्डू।

5. गोंद- हड्डियों का सहारा
परंपरागत उपयोग- सर्दियों में गोंद के लड्डू ताकत और गर्मी देने के लिए खाए जाते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टि- गोंद एक प्राकृतिक रेज़िन है, जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं।
पोषण मूल्य (100 ग्राम में):
कैलोरी 350, प्रोटीन 2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 85 ग्राम, कैल्शियम 40mg
स्वास्थ्य लाभ:
हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है
प्रसव के बाद महिलाओं के लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
कैसे लें: गोंद के लड्डू, दूध या हलवे में।

6. मोरिंगा (सहजन की पत्ती)- मल्टीविटामिन का नैचुरल पैकेट
परंपरागत उपयोग- सहजन की फली और पत्तियाँ दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश में प्रयोग की जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि- मोरिंगा पत्तियों में विटामिन A, C, E, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
पोषण मूल्य (100 ग्राम में): कैलोरी 64, प्रोटीन 9 ग्राम, कैल्शियम 185mg, आयरन 4mg, विटामिन C 51mg
स्वास्थ्य लाभ: खून की कमी (एनीमिया) दूर करता है। ब्लड प्रेशर और शुगर को संतुलित करता है। आँखों और त्वचा के लिए लाभकारी, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक।
कैसे लें: पत्तियों की सब्ज़ी, सूप, चूर्ण या कैप्सूल।
निष्कर्ष हमारे घर की रसोई में छिपे ये सुपरफूड्स न केवल पोषण का खजाना हैं बल्कि बीमारियों से बचाने वाली प्राकृतिक दवा भी हैं। आज जब लोग कृत्रिम सप्लीमेंट्स की ओर भाग रहे हैं, हमें अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर गर्व करना चाहिए और इन्हें रोज़ाना के आहार में शामिल करना चाहिए।
याद रखें- स्वस्थ जीवन का राज हमारी थाली में ही छुपा है।

गाँवों में विज्ञान: ग्रामीण जीवन में बदलाव की नई रोशनी

लेखक: भारत पांडेय, रानीखेत

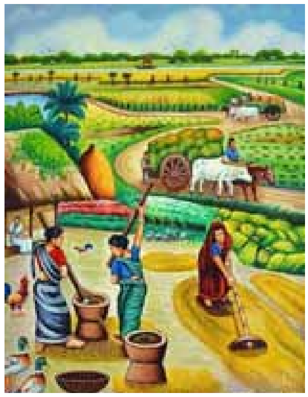

भारत को हमेशा से गाँवों का देश कहा गया है। आज भी हमारी अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गाँवों का जीवन सरल, प्राकृतिक और परंपराओं से भरा हुआ है। लेकिन आधुनिक दुनिया में प्रगति केवल विज्ञान के बिना संभव नहीं है। लंबे समय तक विज्ञान और तकनीक को केवल शहरों तक सीमित माना जाता था- जहाँ स्कूल, उद्योग और प्रयोगशालाएँ थीं। अब धीरे-धीरे विज्ञान गाँवों तक पहुँच रहा है और लोगों के जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है।

आज के गाँवों में परंपरा और विज्ञान दोनों एक साथ चलते दिखाई देते हैं। किसान अभी भी हल से खेत जोतते हैं, लेकिन मौसम की जानकारी मोबाइल फोन से लेते हैं। बच्चे अभी भी लकड़ी की बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रोजेक्टर या टैबलेट से पढ़ाई भी होती है। यह दिखाता है कि विज्ञान गाँवों में अपनी जगह बना रहा है। खेती में विज्ञान का सबसे बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। खेती ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार है। पहले किसान केवल वर्षा और अपने अनुभव पर निर्भर रहते थे। आज विज्ञान की मदद से वे मिट्टी की जाँच करते हैं, अच्छे बीज का उपयोग करते हैं और नई तकनीकें अपनाते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई। अब ड्रोन का इस्तेमाल फसल की निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। इन बदलावों से उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में सुधार होता है। जब विज्ञान खेती का सहारा बनता है, तो यह सिर्फ फसल ही नहीं सुधारता, बल्कि किसानों को आत्मविश्वास भी देता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विज्ञान ने गाँवों में बड़े बदलाव लाए हैं। पहले इलाज के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता था। छोटी बीमारियाँ बड़ी बन जाती थीं क्योंकि इलाज समय पर नहीं मिलता था। अब मोबाइल स्वास्थ्य वैन, टेलीमेडिसिन और गाँव के स्वास्थ्यकर्मी इलाज सीधे घर तक पहुँचा रहे हैं। टीकाकरण ने कई जीवन बचाए हैं।

हाल की महामारी में दवाइयाँ, मास्क और टीके गाँवों तक पहुँचाने में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा में भी बदलाव दिखता है। पहले गाँव के स्कूल केवल ब्लैकबोर्ड और किताबों तक सीमित थे। लेकिन अब स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और ई-लर्निंग गाँवों तक पहुँच चुकी हैं। बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन कक्षाओं में भी शामिल हो रहे हैं। इससे उनके सीखने का तरीका रोचक और आसान हो गया है। सही सहयोग मिलने पर गाँव के बच्चे शहर के बच्चों की तरह सफल हो सकते हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने गाँवों को फायदा पहुँचाया है। पहले कई गाँवों में बिजली नहीं थी। शाम होते ही अंधेरा छा जाता था और बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाती थी। अब सोलर पैनल, बायोगैस और छोटी पवन चक्कियों से गाँवों में रोशनी और ऊर्जा पहुँच रही है। ये साधन स्वच्छ, सस्ते और उपयोगी हैं। विज्ञान ने दिखाया है कि गाँव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पानी की समस्या भी गाँवों में हमेशा गंभीर रही है। कई जगह सूखा पड़ता है, जबकि कुछ जगह बारिश का पानी बेकार चला जाता है। विज्ञान की मदद से अब वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और पानी का पुन: उपयोग किया जा रहा है। इससे पानी बचता है और जीवन आसान होता है।

संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बड़ा बदलाव लाया है। पहले चिट्ठी पहुँचने में हफ्तों लग जाते थे। अब मोबाइल और इंटरनेट से गाँव के लोग तुरंत किसी से भी बात कर सकते हैं। किसान मंडी का भाव देखकर फसल बेचते हैं। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का सामग्री ढूँढते हैं। व्यापारी अपने उत्पाद बड़े बाजारों में बेच सकते हैं। महिलाएँ घर से ही ऑनलाइन बैंकिंग कर सकती हैं। इंटरनेट ने गाँवों के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। फिर भी चुनौतियाँ हैं। हर ग्रामीण आधुनिक साधनों का सही इस्तेमाल नहीं जानता। कई लोगों के पास मशीनें खरीदने या तेज इंटरनेट का साधन नहीं है। कभी-कभी प्रशिक्षण न मिलने की वजह से नई तकनीक का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए विज्ञान के साथ-साथ जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि विज्ञान गाँवों की परंपराओं को नहीं मिटा रहा। लोग अब भी त्यौहार मनाते हैं, लोकगीत गाते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं। साथ ही सोलर लैम्प, मौसम ऐप और मेडिकल किट का उपयोग भी कर रहे हैं। विज्ञान और परंपरा साथ-साथ चल रहे हैं। यही संतुलन गाँवों को विशेष बनाता है। अगर भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो गाँवों का विकास विज्ञान के साथ होना चाहिए। गाँवों में लोग, भूमि और क्षमता हैं। विज्ञान इस शक्ति को सही दिशा दे सकता है। विज्ञान केवल मशीन या आविष्कार नहीं है, यह सोचने, सवाल पूछने और जीवन सुधारने का तरीका है। जब ग्रामीण इस सोच को अपनाएँगे, तो किसी भी चुनौती का सामना कर पाएँगे। भविष्य में ग्रामीण भारत विज्ञान के साथ उज्ज्वल हो सकता है। गाँवों में स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित पानी, बेहतर स्वास्थ्य और आधुनिक शिक्षा होगी। किसान नई तकनीक अपनाएँगे, बच्चे डिजिटल साधनों से पढ़ेंगे और परिवार स्वस्थ जीवन जीएँगे। यह भविष्य दूर नहीं, बल्कि अब से ही शुरू हो चुका है। गाँवों में विज्ञान केवल सुविधा नहीं, बल्कि उम्मीद, प्रगति और सम्मान है। यह सभी को बराबरी का अवसर देता है। गाँव पीछे नहीं हैं, वे कदम दर कदम विज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण भारत में विज्ञान केवल एक साधन नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य का वादा है।

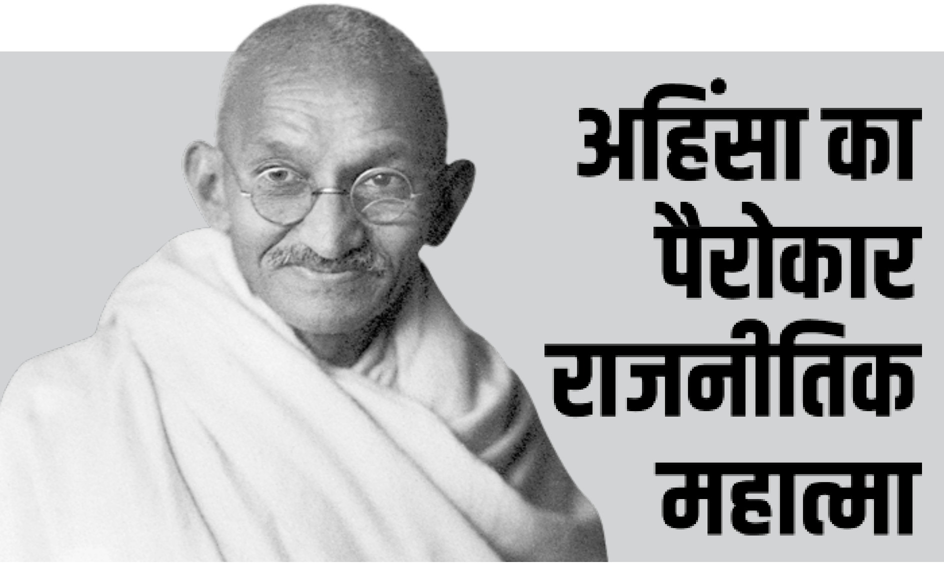

अहिंसा का पैरोकार राजनीतिक महात्मा

गिरेन्द्र सिंह भदौरिया
इन्दौर

आज मैं उस महान विभूति पर अपना मत प्रकट कर रहा हूँ, जो गुजरात की राजकोट रियासत के दीवान की धर्मपत्नी की कोख से जन्मा था, एक अनुमान से कहा जा सकता है कि अपने पिता के दीवान पद पर आसीन होने से जिसे ताउम्र न तो धन की कोई कमी रहती और न किसी सुख सुविधा की। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि जिस गुलामी काल में धनाभाव के कारण तत्कालीन छात्र अपने गाँव में भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, उस समय उन्हें सात समुन्दर पार ब्रिटेन में कानून की शिक्षा दिलवाई गई। जो आजीवन सूट-बूट पहनकर ऐश्वर्य से रह सकता था, उसने जिन्दगी में कभी कपड़े न पहनने का संकल्प ले लिया। कोई विवशता न होते हुए सारे सुखों का इतना बड़ा त्याग साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। इतना ही नहीं भारत को स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी उन्हें किसी भी सर्वोच्च पद पर निर्विरोध विभूषित किया जा सकता था किन्तु किसी भी पद के प्रति आकर्षण न होना उनकी महान विभूति के विशेषण को और भी सार्थक करता है।

जिनकी शिक्षाओं को गांधी दर्शन का नाम मिला जिसे हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं उनके पथ पर चलने वाले किसी भी देश के जुझारू व्यक्तित्व को उस देश का गांधी पुकारकर सम्मानित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला इसके प्रमाण रहे हैं। 'सीमान्त गांधी' या 'सरहदी गांधी' के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनके समान विचारधारा के कारण उन्हें यह उपनाम दिया गया। वह ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त (अब पाकिस्तान में है) के पश्तून थे और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक अहिंसक प्रतिरोध आन्दोलन, 'खुदाई खिदमतगार', का नेतृत्व किया।

जिस मोहनदास को चम्पारण के एक किसान ने बापू कहा तो वह युग का प्यारा बापू हो गया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जिन्हें राष्ट्रपिता कहा तो वह भारत का राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। गुरुदेव कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा तो वह राजनीतिक सन्त के रूप में महात्मा हो गया। विंटन चर्चिल ने जिसे अर्द्ध नग्न फकीर कहा तो 'मजबूरी का नाम महात्मा गांधी' एक लोकोक्त उक्ति बन गया।

हमें विचार करना होगा कुछ तो बात है, जिससे वे हमेशा के लिए अमर हो गए। वे आज भी कीर्तिकाय होकर जीवित हैं। मोहनदास गांधी ने ऐसे काम किए हैं जिनके कारण भारत राष्ट्र उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है।

उनके जीवन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं: महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के ख्यात बन्दरगाह पोरबन्दर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचन्द गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे।

महज 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा पोरबन्दर और राजकोट में हुई। फिर 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लन्दन से वकालत की डिग्री ली।

बैरिस्टर बनने के बाद उन्हें 1893 में एक कानूनी मामले के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ जब उन्हें नस्लभेदी टिप्पणियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को उनके रंग-रूप के कारण संघर्ष करता देख गांधीजी ने उनकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जिन्हें रंग भेद के कारण अपमानित कर ट्रेन से फेंक दिया गया। यही उनके जीवन का वह मोड़ था जिससे गांधी जी की विचारधारा में सत्याग्रह का जन्म हुआ।

20 साल से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में गांधीजी भारत लौटे। देश वापस आते ही गांधी जी अपने देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इसके लिए वह भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से जुड़े और जल्द ही इसके प्रमुख नेता बन गए। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के कई राष्ट्रीय आन्दोलन उनके नेतृत्व में किए गए, जिनसे भारत में पदस्थ गोरों की सरकार ही नहीं अपितु समूची दुनिया प्रभावित रही। इनमें असहयोग आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलन, नमक कानून तोड़ने के लिए दाण्डी यात्रा, भारत छोड़ो आन्दोलन आदि प्रमुख थे।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, सर्वधर्म समभाव, स्वच्छता, अस्पृश्यता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धान्तों को पूरे जीवन में मन से अपनाया। इन सिद्धान्तों का गम्भीर प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ा और जिसे गांधी दर्शन के नाम से जाना गया। उनके त्याग और सिद्धान्तों को जानकर पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ गांधी जी की भक्त बनती गईं। उनके एक आहवान पर समूचा देश खड़ा हो जाता था, दुष्ट अँग्रेजी सरकार उनके कदमों में आ गिरती थी। सच तो यही है कि दूसरी सहस्राब्दी के 1000 सालों में विश्व में उन जैसा राजनीतिक समझ वाला गुणवान व्यक्तित्व पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए सन् 2000 में दुनिया द्वारा महात्मा गांधी को सहस्राब्दी का महानायक माना गया। यह भारत के गौरवशाली इतिहास को और भी

गौरवान्वित करता है।

4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो मैसेज देते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने महात्मा गांधी को देश का पिता (राष्ट्रपिता) कहकर संबोधित किया था। आगे चलकर भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दी। भारत को आजादी दिलाने में जिन महान विभूतियों का नाम आता है उनमें स्वयं का बलिदान करने वाले लाखों उन अमर शहीदों का महत्त्व किसी से किसी भी तरह कम नहीं है। स्वयं के अस्तित्व के बलिदान देने से बड़ा दूसरा कोई बलिदान नहीं हो सकता। जिन माता-पिता ने अपनी सन्तानों को अपनी आँखों से फाँसी पर झूलते हुए देखा। जिन बहनों ने अपने भाई और पतियों को खोया। जिन वीरांगनाओं ने बलि पथ का चयन किया उसकी तुलना किसी भी अन्य त्याग से नहीं की जा सकती। यह परम सत्य है। इसीलिए यह भी सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना भी उचित नहीं होगा, बात इकतरफा नहीं होनी चाहिए परोक्षापरोक्ष सभी के त्याग महत्त्वपूर्ण हैं। यद्यपि अखण्ड भारत के बँटवारे का आरोप व शहीदे आज़म सरदार भगतसिंह की फाँसी टालने के लिए अँग्रेजी सत्ता से कुछ न कहने का आरोप उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते रहे हैं। सम्भवत: इन्हीं कारणों से आक्रोशित नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने आज़ादी मिलने के 5 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को दिल्ली में गोली मार दी।

गोडसे ने अदालत में दिए अपने बयान में कहा कि उसने महात्मा गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गांधीजी की नीतियों ने भारत का विभाजन करवाया और लाखों हिन्दुओं का जीवन बर्बाद किया। गोडसे ने गांधीजी पर मुस्लिम तुष्टिकरण और देश के बँटवारे में भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह गांधीजी की देश सेवा का सम्मान करता है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वे मातृभूमि को तोड़ें। इतना सब कुछ होते हुए भी स्वतन्त्रता प्राप्ति में महात्मा गांधी जी के योगदान को कमतर नहीं आँका जा सकता। गांधी जी की मृत्यु की शोक सूचना सिर्फ भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को शोक में डालने वाली थी। एक ऐसा राजनीतिक सन्त महात्मा जिस पर हर भारतीय गर्व करता है, जिसने विश्व की राजनीति को दिशा दी, आज हमारे बीच में नहीं होते हुए भी है। आओ हम सब उनके सिद्धान्तों पर चल कर उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।

यूकॉस्ट द्वारा 'पर्वतीय भूभाग में जल सुरक्षा एवं जल संसाधन प्रबंधन' विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा जल शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दिनाँक 27.09.2025 को ''पर्वतीय भूभाग में जल सुरक्षा एवं जल संसाधन प्रबंधन'' विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने इस अवसर पर कहा कि परिषद द्वारा उत्तराखंड राज्य के जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन, पुनर्जीवन आदि की दिशा में राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संबंधित विभागों, सामाजिक संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रूप से मिलकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमांत क्षेत्र तक के विद्यार्थियों एवं आमजन मानस हेतु जल जागरुकता एवं जल स्रोतों के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु ऑनलाइन माध्यम से वैज्ञानिक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम का स्वागत संबोधन संयुक्त निदेशक, यूकॉस्ट डॉ. डी. पी. उनियाल ने किया। उन्होंने परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों तथा जल संरक्षण से जुड़ी पहलों पर प्रकाश डाला। यूकॉस्ट के वैज्ञानिक व कार्यक्रम समन्वयक डॉ. भवतोष शर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी का परिचय कराया।

मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गोपाल कृष्ण ने ''पर्वतीय भूभाग में जल सुरक्षा एवं जल संसाधन प्रबंधन'' पर अपने व्याख्यान में जल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जल लिंकिंग स्फीयर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वैश्विक जल वितरण, जल संकट के कारक, जल गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वर्षा वितरण, समस्थानिक (आईसोटोपस) मिश्रण मॉडल, वायुमंडलीय नदियाँ एवं रिवर बैंक फिल्ट्रेशन जैसे विषयों पर विस्तार से बताया।

व्याख्यान के पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित हुआ जिसमें विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों ने विशेषज्ञ से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। यूकॉस्ट के वैज्ञानिक डॉ. भवतोष शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन रावत द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में वैज्ञानिक अधिकारी, डॉ राजेंद्र सिंह राणा, डॉ ओम प्रकाश नौटियाल, परियोजना अधिकारी श्री नरेश गौर, श्री अमित पोखरियाल, डॉ मंजू सुंदरियाल आदि सहित समस्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ग्रुप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीमान्त एवं पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून जिलों के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, यूकॉस्ट के पर्यावरण विज्ञान चेतना केंद्रों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

‘शांति, एकता व विश्वास बढाने में मीडिया की भूमिका’

माउंट आबू में 05 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

प्रजापिता विश्व शांति, एकता व विश्वास के लिए मीडिया की भूमिका विषय पर 5 दिवसीय सेमिनार आयोजित कर रहा है। इस सेमिनार में पत्रकारों को आध्यात्म से जोड़ने और उनको राजयोग अभ्यास कराकर तनावमुक्ति के गुर भी सिखाए जाएंगे। यह सेमिनार 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगा। यह सम्मेलन ‘शांति, एकता व विश्वास बढाने में मीडिया की भूमिका’ विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इस महासम्मेलन में 1500 से अधिक मीडिया कर्मियों के लेने की व्यवस्था की गई है। इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक पत्रकारिता की ओर प्रेरित करना है साथ ही साथ पत्रकारों के मानसिक दबाव को राजयोग के अभ्यास के माध्यम से कम करना है। साथ ही ऐसे लोगों की आवाज को उठाना जो असक्त हैं और अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। यदि पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए तो मीडिया जगत में सच परोसने वालो की संख्या बढ़ सकती है। ब्रह्माकुमारीज मीडियाविंग के मुख्यालय समन्वयक बीके शांतनु भाई के संयोजन में देशभर से चुनिंदा पत्रकारो, मीडिया प्राध्यापको व संस्थान प्रमुखों के माध्यम से मीडिया की वर्तमान दशा व दिशा पर चिंतन के साथ शांति, एकता, विश्वास बढाने के लिए मीडिया के योगदान पर यह सेमिनार आयोजित हो रही है। ब्रह्माकुमारीज मीडियाविंग के चेयरपर्सन बीके करुणा भाई मानते है कि मीडिया अपनी सार्थक जिम्मेदारी निभाता आया है और विचलित हुए बिना राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकारों को आमजन के सामने लाने में मीडिया का हमेशा अहम योगदान है। तभी तो ब्रह्माकुमारीज संस्थान पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता को आध्यात्मिकता से जोड़कर देश विदेश के पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। वर्तमान दौर में मीडिया के माध्यम से परोसे जा रहे सत्य की सारगर्भित विवेचना होने और देश की अर्थव्यवस्था, चुनाव, राजनीति व मीडिया की स्वतंत्रता को भी रेखांकित किया जाता है। मीडिया की विभिन्न चुनोतियो की ओर ध्यानाकर्षण कराने और मिडिया पर आए संकट को भी परिभाषित किया जाएगा। सच यह भी है कि देश मे सच लिखने वाले अच्छे पत्रकारों की भी कमी नही है लेकिन अगर ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाओं के माध्यम से पत्रकारों को समय समय पर मिशनरी पत्रकारिता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता रहा तो अर्द्ध सत्य परोसने वालो की संख्या घट सकती है और सत्य आधारित मूल्यपरक पत्रकारों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रह्माकुमारीज मीडियाविंग के नेशनल कोर्डिनेटर बीके सुशांत भाई युवा पत्रकारों के चरित्रनिर्माण पर जोर देते है, उनका कहना है कि देश और समाज को उन्नत करने के लिए मूल्यो को समझना व उनपर चलना जरूरी है। मीडिया में अपेक्षित सुधार के लिए ब्रह्माकुमारीज के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल मीडिया सेमिनारों की आज के दौर में सबसे ज्यादा आवश्यता है। तभी मीडिया अच्छे काम करके देश व समाज मे अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है। वास्तविकता यह भी है कि लोकतंत्र में मीडिया के महत्व को नकारा नही जा सकता और ब्रह्माकुमारीज के इस विषयक योगदान की सराहना होनी ही चाहिए। क्योंकि ब्रह्माकुमारीज के माध्यम से पत्रकारों को निरन्तर मूल्याधारित पत्रकारिता का प्रशिक्षण देकर हालात बदले जा सकते है। ब्रह्माकुमारीज मिडियविंग मुख्यालय समन्वयक बीके शांतनु मानते है कि पत्रकारों द्वारा की गई सामाजिक सेवा व सामाजिक मूल्यों को बचाये रखने के उनके योगदान को भुलाया नही जा सकता। साथ ही हमे अच्छी सोच पैदा करनी होगी, तभी हम मीडिया को अच्छा बना सकते है।

मीडिया में आये दिन हो रहे बदलाव और उसके प्रभाव को लेकर भी इस सम्मेलन में चर्चा होगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में नए विद्यार्थियों की अपेक्षाओं और इस दिशा में आमजनमानस की सोच को रेखांकित करते हुए बाजारवाद के बाद भी मूल्यों का बचा रहना ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। मीडिया सम्मेलन में देशभर से भाग लेने वाले पत्रकार संकल्प लेते है कि वे ब्रह्माकुमारीज से जाकर अपनी लेखनी के माध्यम से सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि पत्रकारिता में आध्यात्म के समावेश से ही समृद्ध भारत की तस्वीर बनेगी। पत्रकार अपने समाचार के माध्यम से समाज में आशा जगाने वाली सकारात्मक खबरों को प्रस्तुत करने की पहल भी ब्रह्माकुमारीज से प्रेरित होकर करते है। इससे ही मीडिया समाज को मानसिक स्वास्थ्य परोस सकता है। समाज और जीवन को प्रभावित करने वाली जो भी गतिविधियां हमारे समाज में हैं, उसमें समाज को प्रभावित करने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मीडिया समाज के लोग मंगल कार्य में बहुत प्रभावकारी है। जैसे डॉक्टर शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, उसी प्रकार मीडिया मानसिक स्वास्थ्य समाज को दे सकता है।

प्री डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ की वार्ता

उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) शीघ्र होगा शुरू

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में आपदा प्रबन्धन विभाग एवं विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रेषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों जैसे पीएमयू को 31 अक्टूबर, 2025 तक ड्राफ्ट सीईआरसी संचालन मैनुअल और ड्राफ्ट आपातकालीन कार्य योजना तैयार करनी है, को प्रस्तावित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए।

बैठक के दौरान वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू), परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू), और क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (एफपीआईयू) की स्थापना कर दी गई है, जिसमें कुछ पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और भर्ती प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। 29 पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें उल्लेखनीय भौतिक और वित्तीय प्रगति देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शुरू की गई है, और मोबाइल ऐप सुरक्षा ऑडिट के बाद शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही, परियोजना से प्रभावित परिवारों को भूमि मुआवजा प्रदान किया गया है, और शिकायत निवारण तंत्र पूरी तरह कार्यात्मक है।

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड भूकम्प जोखिम मूल्यांकन एवं शमन के सम्बन्ध में बैठक ली। बैठक में आईआईटी रूड़की और वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने कहा कि भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से प्रदेश का एक बड़ा भू-भाग के जोन 5 में है, जिसके कारण यूईआरएएम के उद्देश्य, एक औपचारिक सुरक्षा-संचालित वातावरण तैयार करते हुए भूकंप से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को कम करना, पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के लोगों को भूकम्प जैसी परिस्थितियों के लिए जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए भूकम्प की मॉक ड्रिल के लिए एक दिन निर्धारित करते हुए नियमित रूप से भूकम्प जागरूकता दिवस मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे भूकम्प जैसी परिस्थिति में न्यूनतम मानवीय और आर्थिक नुकसान होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि यूएसडीएमए द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के साथ एक विस्तृत एमओयू किया जाए जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि वाडिया संस्थान ग्लेशियर लेक पर काम कर रहा है तो आईआईटी रूड़की भूकम्प जोखिम मूल्यांकन और शमन पर कार्य कर सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता की दृष्टि से भवन निर्माण के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए जाने चाहिए। उन्होंने भूकम्परोधी भवनों के सम्बन्ध सीबीआरआई के साथ एमओयू किए जाने की आववश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर सचिव श्री विनोद कुमार सुमन एवं अपर सचिव श्री आनन्द स्वरूप सहित आईआईटी रुड़की, वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान और सीबीआरआई के वैज्ञानिक उपस्थित थे।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

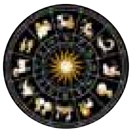
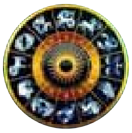
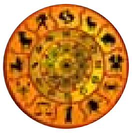

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- घर के बुजुर्गों की बातों को अनदेखा न करें। उनका आशीर्वाद और सहयोग आपको सही रास्ता दिखाएगा। इस समय व्यापार को बढ़ाने के लिए साझेदारी फायदेमंद साबित होगी। नौकरी में मनपसंद जगह पर तबादला होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपको सही हल मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा।

वृषभ राशि- सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में आपके योगदान और लगन की वजह से आपके मान-सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। किसी तरह के निवेश से जुड़ी गतिविधियों को अभी रोक दें, वरना नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। इस समय व्यवस्थित दिनचर्या और संयमित खान-पान को रखना बहुत जरूरी है।

मिथुन राशि- पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान पर अपना ध्यान लगाएं। अपने गुस्से और कड़वी जुबान पर भी लगाम रखें। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति रखें। मशीनरी और मोटर पार्ट्स से संबंधित व्यवसाय में बहुत अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। शादी के बाद के संबंध आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बदलते मौसम से भी अपना बचाव करें।

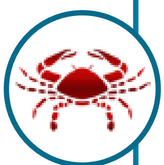

कर्क राशि- आर्थिक समस्या को लेकर घर में कुछ तनाव भी रहने की संभावना है। बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। नौकरीपेशा लोग आज भी बहुत ज्यादा काम के बोझ की वजह से अपने निजी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। खाने-पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें।

सिंह राशि- किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी सोच में बदलाव लाएगी। अपनी चीजों की देखभाल खुद करें, दूसरों से सहयोग की उम्मीद न रखें। बड़े लोगों के साथ मिलते-जुलते समय अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। भाई-बहनों के साथ भी कुछ समय जरूर बिताएं। सरकारी कर्मचारी गैरकानूनी कामों से दूर रहें। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी आएगी।

कन्या राशि- दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद ही अपने कामों को पूरा करें। दोस्त के साथ बातचीत करना आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। व्यवसाय से जुड़ा कोई भी खास काम करते समय जल्दबाजी न करें, पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें। पति-पत्नी आपसी तालमेल से घर की व्यवस्था को भी ठीक बनाए रखेंगे।

तुला राशि- कई मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की भी जरूरत है। बेकार के वाद-विवाद में पड़ने से कोई अपमानजनक स्थिति पैदा हो सकती है। यह समय पेमेंट वसूल करने के लिए सबसे अच्छा है। पति-पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकी आएगी। साथ ही कोई मनोरंजन से जुड़े कामों में समय बीतेगा।

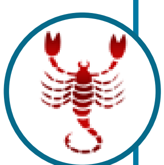

वृश्चिक राशि- आपके लिए कुछ सम्मानजनक और धन से जुड़ी स्थितियां बनेंगी। इस फायदेमंद ग्रह स्थिति का पूरा फायदा लें। आपका विवेक और आदर्शवादिता आपको घर और समाज में मान-सम्मान दिलाएगा। घर में रिश्तेदारों के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को भी शादी से जुड़ी

धनु राशि- युवाओं को भी अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें, क्योंकि आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है। नौकरीपेशा व्यक्ति जल्दी ही अपनी मनचाही जगह प्राप्त करेंगे। दांपत्य संबंध मधुरता पूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंधों में कोई भावनात्मक दूरी आ सकती है, इसलिए एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करें।

मकर राशि- जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मिठास रखने में आपका योगदान जरूरी है। व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों में पैसों का लेन-देन करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखें, क्योंकि धोखा होने की संभावना है। घर के लोग आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। कुछ समय व्यायाम और योगा में भी जरूर बिताएं।

कुंभ राशि- किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपका आत्मविश्वास बनाए रखना आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। लेन-देन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। साझेदारी में कुछ अनबन होने की आशंका है। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर रखने में कुछ दिक्कतें आएंगी।

मीन राशि- परिवार के लोगों या दोस्तों के साथ मनोरंजन में भी कुछ समय बीतेगा। ाइनेंस से जुड़ा कोई रुका काम गति में आ सकता है। मशीनरी जैसे कामों से संबंधित व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होने की संभावना है। किसी बाहरी व्यद्रि की वजह से आपके शादीशुदा जीवन में लड़ाई हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। योग को नियमित करते रहें।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का आएगा दूसरा सीजन', एक्टर ने किया कंफर्म

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो गई है। पहला सीजन हिट होने के बाद, एक्टर रजत बेदी ने कंफर्म किया है कि मेकर्स इसका दूसरा सीजन भी लेकर आने वाले हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में शानदार एंट्री मारी है। उनकी पहली वेब सीरीज बतौर डायरेक्टर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फैंस के बीच हिट हो गई है। सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। अब पहले सीजन की हिट के बाद, मेकर्स इसका दूसरा सीजन भी जल्द लेकर आ रहे हैं।

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सीजन 2 को लेकर क्या बोले रजत बेदी?: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जलज सक्सेना का रोल प्ले कर चुके एक्टर रजत बेदी ने खुद कंफर्म किया है कि मेकर्स दूसरे सीजन पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हां, दूसरा सीजन बन रहा है, इसपर काम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस दूसरे सीजन में मुझे और भी ज्यादा देखेंगे।

'कैसे आर्यन की सीरीज का हिस्सा बने रजत बेदी?: रजत बेदी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वेब सीरीज में शानदार वापसी के बाद सुर्खियों में हैं। यह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली डायरेक्टोरियल ओटीटी सीरीज है। सीरीज में रजत ने जराज सक्सेना का किरदार निभाया है, जो फिल्म माफिया द्वारा बैन किया गया एक एक्टर है। उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें यह रोल कैसे मिला और इस बारे में शाहरुख से उनकी क्या बातचीत हुई। उन्होंने यह भी बताया कि शो में शामिल होने से पहले उन्होंने आर्यन के सामने क्या शर्त रखी थी।

रजत बेदी को कैसे मिला आर्यन खान की सीरीज का ऑफर: डिजिटल कमेंटरी से बात करते हुए रजत बेदी ने कहा कि वह पिछले तीन सालों से काम की तलाश में थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आर्यन उनके लिए कोई रोल सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि आर्यन की प्रोडक्शन टीम ने एक कॉमन दोस्त के जरिए उनसे कनेक्ट किया। उस समय वह कनाडा में थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'आर्यन को यकीन था कि वह मुझे इस रोल में कास्ट करके सही कर रहे हैं क्योंकि जब वह छोटे थे तो उन्होंने 'कोई... मिल गया' फिल्म में मेरा काम देखा था। अगर आप शो देखेंगे तो आपको मेरी जिंदगी से बहुत सारे कनेक्शन दिखेंगे।'

शाहरुख खान संग की थी करियर की शुरुआत: उन्होंने आगे कहा, 'प्री-शो में आर्यन के दोस्तों ने बताया कि वह मुझसे मिलने से पहले बहुत नर्वस था। आर्यन मुझसे मिलने और रोल के बारे में बताने के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहा था, लेकिन बात यह है कि पहली ही मुलाकात में उसने मेरा दिल जीत लिया, जब आर्यन मेरे पास बैठा और मुझे बताया कि वह क्या कर रहा है तो मैं मन में ही सोच लिया था हां बोल दूंगा। मैंने उसे शाहरुख को फोन करने को कहा। बता दें, रजत ने शाहरुख खान की फिल्म 'जमाना दीवाना' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी।

आर्यन खान के सामने रजत बेदी ने रखी थी ये शर्त: उन्होंने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान से बात की और पूछा कि उनका बेटा आर्यन क्या बना रहा है। उन्होंने कहा, 'शाहरुख सर ने मुझसे कहा... देख लो, अगर तुम्हें करना है... मेरा बेटा कुछ बना रहा है।' हालांकि, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम करने के लिए हां कहने से पहले रजत ने आर्यन के सामने शर्त रखी कि वह उनके बेटे को भी अपने साथ रखे। एक्टर ने कहा, 'मैं आपका काम तभी करूंगा, जब आप मेरे बेटे को आपका असिस्टेंट बनने दोगे। मैंने अपने करियर की शुरुआत आपके पिता के साथ की थी। मेरा बेटा भी अपने करियर की शुरुआत आपके साथ करेगा। फिर क्या आर्यन ने हां कह दिया।'

रजत बेदी का बेटा कौन है?: रजत बेदी के दो बच्चे हैं- बेटी वेरा बेदी और बेटा विवान बेदी। दोनों ही मुंबई में आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर में पब्लिक में आने के बाद से ही चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। रजत बेदी के बेटे विवान ने अपने करियर की शुरुआत आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की है।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

Hamari Pahad Ki Matao Dwara
Pyar se Banaya Gaya

BADRI COW GHEE

A2 Protein

Ancient Bellona Method

Beneficial for Health

fssai
22623030001586

Available on
Kumar Sweets

- Sahastradhara Road, Near Crossing
- Dharampur Near LIC Building

Dehradun